भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2165
01 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

डेंगू वैक्सीन का परीक्षण

† 2165. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के पहले डेंगू टीके के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेतृत्व में तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों में प्रतिभागियों का नामांकन लगभग पूरा हो चुका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डेंगू देश में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या का विषय है, जो इस रोग के सबसे अधिक मामलों वाले शीर्ष 30 देशों में शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में वर्तमान में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसका देश के 20 केंद्रों में परीक्षण किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हों, तो आज तक प्राप्त परिणाम क्या रहे तथा तेलंगाना और कर्नाटक के लिए स्वीकृत और व्यय की गई निधि कितनी है;

(च) क्या संपूर्ण देश के कई क्षेत्रों में डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप प्रसारित या सह-प्रसारित होते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हमारे पास उक्त वायरस के सभी चार सीरोटाइप के लिए अच्छी प्रभावकारिता प्राप्त करने वाला एक प्रभावी टीका होना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क), (घ) और (ङ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि इसने "डेंगू टेट्रावैलेंट वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड (रीकॉम्बिनेंट, लियोफिलाइज्ड) -"डेंगीऑल" की एकल खुराक की प्रभावकारिता, प्रतिरक्षाजनकता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए एक चरण-III, बहुकेंद्रीय,

यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड, प्लेसीबो नियंत्रित अध्ययन" शीर्षक से एक नैदानिक परीक्षण किया है। इस परीक्षण में 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक नामांकन पूरा हो चुका है। यह परीक्षण भारत में 20 स्थानों पर किया जा रहा है। इनमें से दो कर्नाटक में और एक तेलंगाना में है। ये स्थान हैं: जेएसएस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मैसूर (कर्नाटक), बैंगलोर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु (कर्नाटक) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबीनगर (तेलंगाना)। परीक्षण के लिए प्रति स्थान अनुमानित बजट 1.3 से 1.5 करोड़ रुपये है।

(ख), (ग), (च) और (छ): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के माध्यम से कुल 5,73,563 प्रयोगशाला-पुष्ट (एल फॉर्म) डेंगू के मामले दर्ज किए गए।

आईसीएमआर के अनुसार, डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप (DENV-1, DENV-2, DENV-3, और DENV-4) भारत में प्रसारित और सह-प्रसारित होते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कई सीरोटाइप मौजूद हो सकते हैं और एक ही समय में एक ही व्यक्ति को संक्रमित भी कर सकते हैं। इसलिए, सभी चारों सीरोटाइप के विरुद्ध टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए, उन विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागियों को परीक्षण में शामिल होने के लिए नामित किया गया है, जहाँ ये चारों सीरोटाइप प्रसारित होते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) देश भर में डेंगू के प्रकोप की स्थिति की नियमित निगरानी करते हैं ताकि रोग की स्थिति का आकलन, तत्परता, तकनीकी मार्गदर्शन और राज्यों को संवेदनशील कर के पूर्व चेतावनी दी जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डेंगू नियंत्रण गतिविधियों जैसे महामारी के लिए तत्परता, निगरानी, केस प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण (घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं, आशा की भागीदारी, कीटनाशक, फॉगिंग मशीनों का प्रावधान), प्रशिक्षण, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण, जागरूकता गतिविधियाँ आदि के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। डेंगू की निगरानी और निःशुल्क निदान के लिए, देश भर में प्रयोगशाला सुविधाओं वाले प्रहरी निगरानी अस्पतालों और उन्नत नैदानिक सुविधाओं वाली शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है। आईसीएमआर के अनुसार, डेंगू के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीके नहीं हैं और उपचार सहायक रूप में है। भारत सरकार ने विशेषज्ञों के परामर्श से डेंगू के मामलों के उपचार/प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए हैं और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए हैं। ये दिशानिर्देश मामलों के उपचार/प्रबंधन के लिए अस्पतालों की तैयारी पर ज़ोर देते हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण, जिसमें मामलों का प्रबंधन भी शामिल है, के लिए परामर्श जारी किए गए हैं।

*****